केंद्रीय बिजली मंत्री ने कहा- 2022 तक एक लाख 75 हजाए मेगावॉट नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन का लक्ष्य अभ्सय ऊर्जा पांच साल में क्षमता से ज्यादा
नई दिल्ली | विशेष संवाददाता
केंद्रीय बिजली मंत्री पीयूष गोयल ने सोमवार को कहा कि अक्षय ऊर्जा की स्थापित क्षमता अगले पांच वर्ष में थर्मल पावर की क्षमता से अधिक हो जाएगी। सरकार ने 2022 तक एक लाख 75 हजार मेगावॉट नवीकरणीय ऊर्जा के उत्पादन का लक्ष्य रखा है। नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में यही रफ्तार रही, तो लक्ष्य हासिल करना तय है।

बिजली, कोयला, नवीकरणीय ऊर्जा और खान मंत्रालय की तीन वर्ष की उपलब्धियों की जानकारी देते हुए गोयल ने कहा कि सरकार 18,452 गांवों में से 13,630 गांवों का विद्युतीकरण कर चुकी है। करीब एक हजार गांवों में बसावट नहीं है। बाकी बचे साढ़े तीन हजार गांवों का विद्युतीकरण इस साल के अंत तक कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि 2022 तक हर घर तक बिजली पहुंच जाएगी।

पटरी पर लाने की कोशिश : पीयूष गोयल ने कहा कि मंत्रालय थर्मल और पन बिजली क्षेत्र में अटकी परियोजाओं को पटरी पर लाने की कोशिश कर रहा है। उन्होंने कहा कि मंत्रालय थर्मल पावर प्रोजेक्ट के ॠण संकट के समाधान के करीब है। साढ़े ग्यारह हजार मेगावॉट की पनबिजली परियोजनाओं पर भी काम चर रहा है। बिजली मंत्रालय और नीति आयोग मिलकर 25 वर्ष के लिए ऊर्जा सुरक्षा नीति का भी मसौदा बना रहा है।


नई दिल्ली में सोमवार को प्रेसवारा के दौरान केंद्रीय मंत्री पीयूप गोयल। $\bullet$ प्रद्र गोशाला में बायोगैस संयंत्र बोटलिंग प्लांट भी लगेंगे बिजली मंत्री ने सभी बड़ी गोशालाओं में बायोगैस प्लांट लगाने का ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि बायोगैस में रसोई गेस के उत्पादन की काफी सभावनाएं हैं। बड़ी गोशालाओं में बायोगैसे के संयंग्र लगने से आमदनी होगी और देश में ईधन की जरूरतों को भी पूरा किया जा सकेगा।

गोयल ने कहा कि बड़ी गोशालाओं में बारोगेगे के बोटालंग प्लांट भी लगाए जाएंगे। ताकि, गोशाला में पैदा होने वाली रसोई गैस को दूसरी जगहों पर इसेमाल किया जा सके। नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के मुताबिक देश में प्रति वर्ष 50 करोड़ टन बायोमॉस की उपलब्धता है।

## बिहारके प्रस्साव को मंजूटी देने को तैयाए

गोयल ने कहा कि बिहार सरकार राज्य में सौर ऊर्जा को बढाने के लिए जितने भी प्रस्ताव भेजेगी, केंद्र उ न प्रस्तवों को मंजूरी देने के लिए तैयार है। बिहार सरकार घरों, कार्यालयों और औद्योगिक इकाइयों की छतों पर सौर ऊर्जा के रुफटटप लगाने के साथ किसानों को ऑफग्रिड बिजली देने के लिए जो प्रस्ताव भेजेगी, केंद्र सरकार उन्हें जरूर मंजूरी देगी।

